श्री हुसैन दलवई : सर, कन्विक्शन रेट इतना कम है, महाराष्ट्र का कन्विक्शन रेट 7 प्रतिशत है। यू.पी. में कन्विक्शन रेट 50.7 प्रतिशत है। देखना यह चाहिए कि इसके बारे में क्या किया गया ? किसी तरह से भी दलितों को राहत और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I am allowing the Special Mentions to be laid on the Table.

SPECIAL MENTIONS*

Demand for installing Braille Boards in National Heritage Monuments

DR. KANWAR DEEP SINGH (West Bengal): Sir, first of all, I would like to praise the effort of Superintendent Archaeologist, Delhi, for installing Braille Boards for visually impaired in the various culturally and historically significant monuments around Delhi. This is a brilliant step that will help visually impaired tourists and visitors a lot. However, I believe this should not just be the effort of one Government employee. With the world's second largest population, India retains the unfortunate distinction of having the largest number of people with visual impairment globally. Some estimates put the figure of blind population in India over 50 million. That being said, it is the responsibility of the Government to aid its disadvantaged population in any way possible. All of these visually impaired tourists are helpless in important national heritage monuments with no information to tell them about their historical significance or even for the most mundane part of finding the direction to the restroom. Most of us take these things to be granted. However, for a visually impaired person, touring a place of national heritage becomes impossible without these aids. Thus the Ministry of Tourism along with the Archaeological Society of India should take the limited initiative of Superintendent Archaeologist, Delhi, throughout the country in every possible national heritage monument.

Demand to run Tulsi Express train daily and extend Intercity Express from Banda to Kanpur upto Lucknow

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय मुम्बई से वाया झांसी-बांदा, मानिकपुर के बीच प्रतिदिन चलने वाले हज़ारों यात्रियों को ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिलाना चाहता हूं । उक्त रेलवे मार्ग पर केवल एक ट्रेन तुलसी एक्सप्रेस नं, 11069-11070 साप्ताहिक इलाहाबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनल (मुम्बई) के बीच चल रही है, जिससे हज़ारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं मांग करता करता हूं कि तुलसी एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाए जिससे कर्वी, अतर्रा, बांदा, महोबा, हरपालपुर, मऊरानीपुर के यात्रियों को मुम्बई की तरफ जाने में ट्रेन की सुविधा मिल सके तथा बांदा-कानपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी

---

*Laid on the Table.

एक्सप्रेस ट्रेन को लखनऊ तक चलाया जाए। साथ ही बांदा-खैराड़ा के बीच रेलवे क्रॉसिंग नं. सी 452 के आगे महोबा-दुरेड़ी रोड़ पर नया रेलवे फाटक बनाया जाए, जिससे नवोदय विद्यालय तथा एकलव्य डिग्री कॉलेज के छात्रों को आने-जाने में कठिनाई न हो ।

मैं रेलमंत्री से मांग करता हूं कि इलाहाबाद-मुम्बई के बीच चलने वाली तुलसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को प्रतिदिन चलाए जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। बांदा-कानपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लखनऊ तक चलाया जाए और बांदा-खैराड़ा के बीच रेलवे क्रॉसिंग नं. सी 452 के आगे महोबा-दुरेड़ी रोड पर नया फाटक बनवाने की कृपा करें।

Demand to take strict measures to stop human trafficking in the country

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हमारे भारत में विषमताओं का बोलबाला इस हद तक बढ़ गया है कि भूमि, सम्पत्ति, पशुओं और साग-सब्जियों के साथ-साथ अब गरीब मजबूर व्यक्तियों और बच्चों की भी, धन अर्जित करने हेतु, खरीद-फरोख्त का घिनौना कार्य खुले आम हो रहा है। हद इतनी हो गयी है कि मासूम बच्चों, बच्चियों और विकलागों का बहुत ही थोड़ी रकम में घरेलू कामकाज, यौन-शोषण करने ओर भीख मंगवाने हेतु प्रयोग करते हैं। इस प्रकार खरीदे गए बच्चों के मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इससे पूरी मानवीय जातियां शर्मिदां हो रही हैं। वही चिंता का विषय यह भी है कि यह जो व्यक्तियों और बच्चों की खरीद-फरोख्त हो रही है, वह अधिकाशं दलित और पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों से संबंधित है। 67 वर्ष के बाद भी आर्थिक संकट इतना गंभीर है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। इस गंभीर समस्या पर देश की सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से पूरज़ोर अपील करता हूं कि शीघ्र ही इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए तथा इस खरीद-फरोख्त की अमानवीय प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।

Demand to review the merger of Public Sector Banks

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, the initiative to amalgamate certain public sector banks needs the rethink. Each and every bank, however small or big it may be, is having its own history, character, approach and leading to competition and also choice to account holders. Union Government and the Reserve Bank of India are now intending to encourage launching of new small banks. The banking needs of rural and urban population across the nation are manifold, since the delivery of various welfare benefits including the direct transfer besides linking with Aadhar. Some corporations at Union Government level and of State Governments like Electricity Boards have been divided into separate entities to look after the needs of generation, transmission and distribution and showing useful results. Within major banks, these were several subsidiary units to look after different needs. Keeping these factors and global experiences in view, I urge upon the Union Finance Ministry to revisit and evaluate deeply before any further move for merger of certain public sector banks.